हजीरा सहित एच बी जे पाइपलाइन के सभी संयंत्रों में उत्पादन में गिरावट आई।

(ii) विद्युत एवं उपस्कर समस्याओं, कच्चे माल की कमी तथा श्रमिक समस्या के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और दो रुग्ण कम्पनियों अर्थात् फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० और निजी क्षेत्र में जुआरी इंडस्ट्रीज लि०, टाटा कैमिकल्स लि०, कृषक भारती कोआपरेटिव लि०, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०, विस्तार, गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी लिमिटेड सिक्का में उत्पादन प्रभावित हुआ।

(iii) दिसम्बर में यूरान में ओ एन जी सी बन्द होने के कारण रबी 1998-99 में उत्पादन प्रभावित होगा जिससे राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० में उत्पादन पर असर पड़ेगा तथा मार्च, 99 में एच बी जे पाइपलाइन पर सभी उर्वरक संयंत्र प्रभावित होंगे।

(iv) म्यूरिएट आफ पोटाश के अपेक्षाकृत कम आयात स्तर के कारण मुख्य रूप से काम्पलैक्स उर्वरकों के उत्पादन में कमी आई। रबी में स्थिति के सुधरने की आशा है।

(घ) उर्वरक उत्पादन सामान्य रूप से बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं।

(i) नए संयंत्र स्थापित करने/विद्यमान संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत माल का निःशुल्क आयात।

(ii) उर्वरक परियोजनाओं के लिए पूंजी माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को सम्भावित निर्यात लाभ बशर्ते इस तरह की आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के अंतर्गत की जा रही हो।

(iii) उर्वरक कच्चे माल और मध्यवर्तियों का निःशुल्क आयात।

(iv) प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता योजना जो इस समय यूरिया पर लागू है के अंतर्गत उद्यमियों को निवेश पर उचित लाभ।

(ङ) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिसका सरकारी खाते में आयात किया जाता है। अन्य प्रमुख उर्वरकों अर्थात् डी ए पी और एम ओ पी जो नियंत्रणमुक्त है, के आयात निजी व्यापार खाते में किए जाते हैं। मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए यूरिया का आयात किया जाता है।

उर्वरक की उत्पादन लागत में कमी

2173. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करके इनकी उत्पादन लागत कम किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) और (ख) यूरिया निर्माता इकाइयों की स्थापना निर्धारित दैनिक दर क्षमता पर की जाती है। दर क्षमता स्तर पर संयंत्र का प्रचालन सर्वाधिक मितव्ययी प्रचालन है। संयंत्र का नवीनीकरण करके दर क्षमता में वृद्धि किये बिना दर क्षमता स्तर से अधिक उत्पादन करना संभव नहीं है। तथापि, विभिन्न बाधाओं जैसे इनपुटों की आपूर्ति में बाधा, यांत्रिक खराबियों आदि के कारण दर क्षमता स्तर पर इन संयंत्रों का निरन्तर प्रचालन करना संभव नहीं है। ऐसे मामलों में उत्पादन लागत में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो जाती है।

तथापि, यूरिया के मामले के विपरीत फास्फेटिक उर्वरकों के मामले में परिवर्ती लागत कुल उत्पादन लागत का 80 से 85 % होता है। अतः उत्पादन की लागत पर उत्पादन स्तर में किसी परिवर्तन का प्रभाव उतना ही नहीं होगा जैसा कि यूरिया के मामले में होगा।

(ग) और (घ) इस तरह के किसी अध्ययन को आवश्यक नहीं समझा गया है।

Cancellation of DAP Import Contracts

2174. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cancellation of DAP import contracts worth 1.25 lakh tonnes during the last six months has led to shortage of phosphates in the Kharif season,

(b) if so, the reasons for these cancellations;

(c) whether there were any malafides in these cancellations; and

(d) if so, what action has been taken or is proposed to be taken against the erring persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) to (c) DAP is a decontrolled fertiliser. The demand and supply of DAP is regulated by the market forces depending upon the rates of concession and Maximum Retail Price (MRP) fixed by the Government under the Concession Scheme. There were no shortages of DAP during the Kharif season. For Rabi'98-99, the Government had decided first in August'98 to fix the rates of concession alone and leave MRPs in respect of DAP and other decontrolled fertilisers to the market forces. But the policy was rolled back in September'98 in the interest of the farmers as the market determined MRPs of DAP were reported to settle at much higher levels than anticipated. The change of policy resulted in cancellation of nearly 1.30 lakh MTs of imports of DAP for Rabi'98-99. The cancellations were made by the importers on their own accord and based on their commercial judgement.

Despite cancellation of imports, overall availability of DAP for the Rabi season will be adequate to meet the projected requirement of the States for the season at the macro level. The main reasons for the shortages which were/are being experienced in a few States are on account of the increase in the peak demand for DAP due to increase in the area under sowing because of untimely rains as well as the bunching of DAP vessels at Vizag and JNPT ports. The cyclone at the East Coast also affected the despatches from Vizag port for a fortnight.

(d) Question doesn't arise.

यूरिया उत्पादकों को दी जाने वाली राज-सहायता के लंबित पड़े मामले

2175. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 नवम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय में निजी क्षेत्र के यूरिया उत्पादकों को राज-सहायता प्रदान किए जाने संबंधी कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) इन आवेदन-पत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है और लंबित पड़े आवेदन-पत्रों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मामलों में विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या इस संबंध में मंत्रालय को सांसदों की ओर से पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है और लंबित पड़े आवेदन-पत्रों के संबंध में कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी; यदि नहीं, तो तो उसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) से (घ) 30.11.98 को निजी क्षेत्र के आठ यूरिया निर्माता एककों के 246.49 करोड़ रुपए के दावे भुगतान के लिए लम्बित पड़े थे। इसमें से 221.63 करोड़ रुपए के नियमित दावों का निपटान कर दिया गया है। इन एककों में से 7 एकक 24.86 करोड़ रुपए के पूरक दावे पर्याप्त बचत प्रावधान के कारण लम्बित पड़े हैं। इन दावों का निपटान अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने के पश्चात किया जाएगा।

Murate of Potash for A.P.

2176. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Andhra Pradesh Government has sought 45,000 tonnes of murate of potash immediately;